PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 025
दि. 25.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रूबियो के बयान पर भड़का ईरान, अमेरिका को खूब सुनाया; ऊर्जा पर भारत को समर्थन

भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 'ऊर्जा बाजार को बंधक' वाली टिप्पणी पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बयान जारी कर आरोपों को खारिज किया और कहा कि अमेरिका के प्रतिबंध ही वैश्विक ऊर्जा संकट की असली वजह हैं।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईरानी दूतावास ने भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 'बंधक' टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया है। एक प्रेस बयान जारी कर उनके दावे को सिरे से खारिज किया है।

बयान विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किया गया है, जिसके मुताबिक, 'भारत स्थित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दूतावास, अमेरिकी विदेश मंत्री की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करता है। देश यह स्पष्ट करता है कि ऐसे आरोप क्षेत्र की वास्तविकताओं को तोड़-मरोड़कर पेश करने तथा अमेरिका और इजरायली शासन की अस्थिरता फैलाने वाली नीतियों से ध्यान भटकाने का स्पष्ट प्रयास हैं।'

दरअसल, 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगट ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, 'विदेश मंत्री रूबियो और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को वैश्विक ऊर्जा 'बाजार को बंधक' बनाने की इजाजत नहीं देगा, और इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों में भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने की क्षमता है।'

'ईरान भारत को ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार'

ईरान ने अपने प्रेस नोट में आगे इसी पर अपनी बात स्पष्ट की। आगे लिखा कि विश्व के प्रमुख तेल और ऊर्जा निर्यातकों में से एक होने के नाते, ईरान हमेशा भारत सहित सभी देशों को अपने ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहा है। हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा बाजार को जिस चीज ने बंधक बनाकर रखा है, वह ईरान के तेल निर्यात पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 'अवैध और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध' हैं। ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए केवल ईरानी जनता पर आर्थिक दबाव बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।

ईरान बोला- अमेरिकी पाबंदी का आम लोगों पर पड़ रहा असर

बयान में इस पाबंदी का ईरान के आम लोगों पर पड़ने वाले असर का जिक्र है। आगे कहा गया, 'तेल प्रतिबंध, पिछले 47 वर्षों में अमेरिकी

सरकार द्वारा ईरानी जनता पर लगाए गए व्यापक शत्रुतापूर्ण दबावों और कार्रवाइयों का केवल एक छोटा हिस्सा हैं। इन कदमों में दवाओं पर प्रतिबंध और ईरानी मरीजों की आवश्यक दवाओं और जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच सीमित करना भी शामिल रहा है, जिसके कारण दुर्भाग्यवश कई निर्दोष मरीजों की जान खतरे में पड़ी और व्यापक मानवीय पीड़ा उत्पन्न हुई।'

परमाणु कार्यक्रम पर क्या बोला ईरान

इस बयान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर नीति भी स्पष्ट की गई है। कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री के दावों के संबंध में, इस्लामी गणराज्य ईरान एक बार फिर याद दिलाता है कि परमाणु अप्रसार संधि का एक प्रतिबद्ध सदस्य होने के नाते उसने लगातार यह स्पष्ट किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में है। अब तक आईएईए ने ईरान की परमाणु गतिविधियों में किसी भी प्रकार का बदलाव न तो देखा है और न ही उसकी कोई रिपोर्ट दी है।

रूबियो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार (23 मई) को उन्होंने यात्रा की शुरूआत कोलकाता से की। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से लेकर वैश्विक मुद्दों पर गंभीर मंत्रणा हुई।

कंचनजंगा, सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक- प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, सिक्किम के राज्य बनने के 51वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर पीएम मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा लिखित एक लेख साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में कंचनजंगा का विशेष जिक्र किया गया है और इसे सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक बताया गया है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया,"जैसे ही सिक्किम अपने राज्य के दर्जे के 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कंचनजंगा के बारे में लिखा है, और इसकी प्रशंसा करते हुए इसे सिक्किम की भूमि, उसकी स्मृतियों और उसकी चेतना का रक्षक बताया है।

उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कंचनजंगा के पांच रत्न राज्य की यात्रा को लगातार उज्ज्वल बना रहे हैं, और 'विकसित सिक्किम 2047' की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि कंचनजंगा, जिसे "पर्वत श्रृंखला" कहा जाता है, हमारी कल्पना में लुंगता प्रार्थना झंडों, बादलों और बर्फ से ढकी दूर स्थित हिमालयी चोटियों के रूप में उभरता है। सिक्किम की लगभग एक चौथाई भूमि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। सदियों से, कंचनजंगा स्थानीय समुदायों की लोककथाओं में एक पवित्र सभ्यतागत शक्ति के रूप में विराजमान रहा है।

संसदीय समिति के अध्ययन दौरे पर नहीं जाएंगे राठौड़, पीएम के ईंधन बचाने के आ'ान के बाद पंजाब सीएम को लिखा पत्र

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का 30 मई से 4 जून तक श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला जाने का था कार्यक्रम.

(जीएनएस)।

जयपुरः दुनियाभर में ईंधन संकट के खतरे के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की बचत करने का आ'ान किया है. इसके चलते राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने 30 मई से 4 जून तक संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल होने से इनकार किया है. उनका संसदीय समिति के अध्ययन दौरे पर श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला जाने का कार्यक्रम था. जिसके लिए पहले उन्होंने सहमति भी दी थी.

पीएम की अपील का हवाला, सीएम को लिखा पत्र : उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, वाहनों का काफिला कम करने, वर्क फ्रॉम होम का प्रयास करने, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कम करने और वर्चुअल मीटिंग का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई है.

पहले दौरे के लिए दी सहमति : मदन राठौड़ ने इस पत्र में आगे लिखा कि उन्होंने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल होने की पूर्व सहमति दी थी. हालांकि, अब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आ'ान के कारण उन्होंने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है. संसदीय समिति का अध्ययन दौरा 30 मई से 4 जून 2026 तक होना है. जिसमें श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला का दौरा प्रस्तावित है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा उत्तर प्रदेश सीएम योगी

लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में 'आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति-2026' को लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेवाओं के समन्वय से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष सेवाओं को आधुनिक प्रबंधन, गुणवत्ता मानकों और पर्यटन से जोड़ते हुए ऐसा मॉडल तैयार किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार और निवेश को भी नई गति मिले।

'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'

राहुल गांधी के 'पीएम मोदी की विदाई तय' वाले बयान को लेकर बड़ा बवाल मच गया है. पीयूष गोयल ने कहा कि क्ठउक्र गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी.

(जीएनएस)।

कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है. इस पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीयूष गोयल ने रविवार (24 मई) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. यह कोई साधारण बयान नहीं है बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है.

वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं- पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल

गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते. राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है?

'भारत में आग लगाने की साजिश'

उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता समझदार है. वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूलकिट गैंग को अच्छे से समझती है. जनता ने बार-बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है. क्ठउक्र गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे, तीन दिवसीय दौरे में होगा बैठकों का दौर

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत तीन दिवसीय दौर पर रविवार को लखनऊ पहुंचे हैं। तीन दिवसीय दौर पर भागवत संघ की कई बैठक करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में संघ के कामकाज अभियान पर चर्चा करेंगे।

भागवत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले संघ की तैयारी की समीक्षा करने के साथ प्रदेश सरकार से लेकर संगठन तक के कामकाज की समीक्षा के तहत प्रचारकों से फीडबैक लेगें, जिससे कि आगे की रूपरेखा तय की जाएगी।

'कंप्रोमाइज्ड' प्रधानमंत्री 'करीबी मित्र' को खुश करने में लगे हैं : रूबियो के बयान पर बोलेकांग्रेस के दिग्गज जयराम रमेश

(जीएनएस)।

नयी दिल्ली, कांग्रेस ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

विपक्षी पार्टी ने साथ ही यह आरोप भी लगाया कि "कंप्रोमाइज्ड पीएम" अपने "करीबी मित्र" को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने "जनविरोधी" और "खतरनाक" उस भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को निरस्त करने का साहस क्यों नहीं दिखाया।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका से रिकॉर्ड आयात करने पर सहमति क्यों जताई, जबकि प्रधानमंत्री ने पहले ही नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घरेलू ईंधन की खपत और विदेश यात्राएं कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने पूछा, "क्या अमेरिका से आयात में यह भारी वृद्धि रुपये की गिरावट को और तेज नहीं करेगी?"

रमेश ने 'एक्स' पर कहा, "10 मई 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:37 बजे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सबसे पहले युद्धविराम की घोषणा की थी, जिससे 'ऑपरेशन सिंदूर' अप्रत्याशित रूप से रुक गया। उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के कारण ही यह युद्धविराम संभव हो पाया।"

उन्होंने कहा कि 21 मई 2026 को रूबियो फिर सबसे पहले यह घोषणा करने वाले व्यक्ति बने कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत यात्रा पर आएंगे। उन्होंने कहा कि यह तब हुआ, जब भारत और वेनेजुएला ने स्वयं इस खबर का संकेत तक नहीं दिया था या इसकी पुष्टि नहीं की थी।

रमेश ने कहा, 'आज रूबियो ने एक बार फिर 'एक्स' पर यह बयान देकर देश को चौंका दिया है कि मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।"

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 26 तक भारत का वार्षिक आयात 52.9 अरब डॉलर है और रूबियो के बयान का अर्थ है कि भारत को अमेरिका से अपना वार्षिक आयात दोगुना करना पड़ेगा।

रमेश ने कहा, "इस नए घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री से हमारे पांच सीधे सवाल हैं – अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के बाद, जिसमें ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया गया था।

पीएम के मुरीद हुए शशि थरूर, मालदीव से संबंध सुधार को बताया मास्टरस्ट्रोक

फ्लैचर स्कूल में दिए अपने एक भाषण में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मालदीव मुद्दे पर भारत की कूटनीति का जिक्र किया. 'क्ल्ल्र्ि ड४३' अभियान के बावजूद पानी संकट के समय भारत की मदद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भरोसा भाषणों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से बनता है.

(जीएनएस)।

राजनीति में अक्सर पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बयान चर्चा का बड़ा विषय बन जाते हैं. इस बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बयान सुर्खियों में है. मालदीव के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए थरूर ने ऐसा उदाहरण दिया, जिसे कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की अप्रत्यक्ष सराहना के तौर पर देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुश्किल हालात में मदद करके कैसे देशों के बीच भरोसा मजबूत होता है.

शशि थरूर ने अमेरिका के फ्लेचर स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान मालदीव का 'India Out' वाला पूरा किस्सा सुनाया. उनके ऑफिस की ओर से साझा किए गए वीडियो में थरूर ने कहा कि एक समय मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल था, लेकिन संकट के वक्त भारत ने बिना किसी शर्त मदद की. उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसे भारत की पड़ोसी देशों के साथ अपनाई गई नीति के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है.

थरूर ने उस दौर को याद किया जब नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे. मुइज्जू ने चुनाव के दौरान 'क्ल्ल्र्ि ड४३' अभियान चलाया था. बाद में उनकी सरकार ने कुछ भारतीय कर्मियों की वापसी की बात कही और भारत से जुड़े कुछ समझौतों की समीक्षा भी शुरू हुई. जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा था.

थरूर ने बताया कि इसी दौरान मालदीव की राजधानी माले में पानी साफ करने वाला मुख्य डिसैलिनेशन प्लांट खराब हो गया, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि भारत ने बिना देर किए लाखों लीटर पीने का पानी भेजा और बदले में कुछ नहीं मांगा. थरूर के मुताबिक, यही तरीका भरोसा बनाने का होता है. उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़े होने से मजबूत होते हैं.

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ राष्ट्रमंडल खेलों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

(एजेंसी)।

फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण में आज देशभर में 8,000 से अधिक स्थानों पर भारी भागीदारी देखी गई, जो राष्ट्रमंडल खेल दिवस का स्मरणोत्सव मनाता है और अहमदाबाद में होने वाले ऐतिहासिक 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की ओर गति प्रदान करता है।

अहमदाबाद के प्रतिष्ठित साबरमती नदी तट से राष्ट्रीय समारोहों का नेतृत्व करते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, गुजरात के उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने 5,000 साइकिल चालकों, एथलीटों, युवा स्वयंसेवकों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के साथ सामुदायिक भागीदारी और खेल भावना का एक जीवंत प्रदर्शन किया।

अहमदाबाद संस्करण, जिसका विषय "एक स्वस्थ भारत के लिए एक नया प्रतीक - 2030 तक साइकिल चलाना" था, में योग और जुम्बा प्रदर्शनों के साथ-साथ एक भव्य 5 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसने साबरमती नदी तट को फिटनेस, संस्कृति और भारत के खेल विकास के उत्सव में बदल दिया।

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण डॉ. मांडविया द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन था, जिसमें भारत की खेल उपलब्धियों, खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल अवसंरचना के विकास और 2030 में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में देश के विस्तारित खेल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया।

इस आयोजन में पिकलबॉल, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और कई सहभागिता आधारित सामुदायिक खेलों सहित कई प्रकार की आकर्षक गतिविधियां भी शामिल थीं, जिससे सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए एक उत्सव जैसा माहौल बन गया।

अभिनेता आयुष्मान खुराना पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और ओलंपियनों जैसे गुरजीत कौर, रजनी एतिमार्पु, सोनिका तांडी, अंजुम मौदगिल, अंकुर मित्तल और तृप्ति मुगंडे के साथ शामिल हुए, जिन्होंने युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया और भारत के युवाओं के बीच फिटनेस और खेल की बढ़ती संस्कृति को मजबूत किया।

इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति और खेल जगत के नेता भी उपस्थित थे, जिनमें भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटेल; ओलंपिक निशानेबाज और चैंपियनशिप पदक विजेता गगन नारंग; खेलो इंडिया के उप महानिदेशक श्री मयंक श्रीवास्तव; और ओलंपियन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला शामिल थे।

इस आयोजन का एक विशेष सांस्कृतिक आकर्षण गरबा की पारंपरिक भावना को योग के विज्ञान के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया एक अनूठा प्रदर्शन था, जिसे प्रसिद्ध कलाकार श्री अनीश रंगरेज ने प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के डॉ. पवन कुमार ने समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य परामर्श और मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

2030 में होने वाले ऐतिहासिक शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की व्यापक तैयारियों के तहत, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) जनभागीदारी को गहरा करने और भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश भर में भव्य, अंतःक्रियात्मक और समुदाय-संचालित पहलों का आयोजन जारी रखेगा।

देशव्यापी समारोहों का उद्देश्य राष्ट्रमंडल खेलों के आंदोलन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है, साथ ही युवाओं को फिटनेस, खेल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा, 'आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम साइकिल पर आधारित फिट इंडिया संडे के 75वें संस्करण के साथ-साथ राष्ट्रमंडल खेलों का दिवस भी मना रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, और इससे भी अधिक खुशी इस बात की है कि हजारों लोग सुबह-सुबह फिटनेस और राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं।'

'एक स्वस्थ समाज एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। यदि हम वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस को प्राथमिकता देनी होगी। साइकिल चलाना केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। यह हमें फिट रखता है, प्रदूषण कम करता है और ईंधन बचाने में मदद करता है, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ईंधन खपत कम करने की अपील के अनुरूप भी है। अपने दैनिक जीवन में, चाहे कम दूरी के लिए ही क्यों न हो, साइकिल चलाने को अपनाकर हम एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।'

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, 'आज अहमदाबाद शहर में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह रौनक छा गई और गुजरात की जनता की इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखकर मैं बेहद खुश हूं। हजारों नागरिकों का सुबह-सुबह फिटनेस और खेलकूद के लिए बाहर निकलना स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह को दर्शाता है।'

अहमदाबाद में देखी गई व्यापक भागीदारी ने गुजरात भर में खेल और फिटनेस के प्रति बढ़ते उत्साह को भी प्रतिबिंबित किया, जो भविष्य में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए राज्य की तत्परता को रेखांकित करता है।

नागरिकों, खिलाड़ियों, युवा स्वयंसेवकों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति ने इस क्षेत्र में खेल संस्कृति के तीव्र विकास को प्रदर्शित किया और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में अहमदाबाद के उभरने को मजबूत किया।

अभिनेता और फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना ने कहा, 'आज यहां हर उम्र के लोगों को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, जो भरपूर उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। फिट इंडिया और आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 के बीच यह सहयोग बहुत ही शानदार है क्योंकि यह युवा भारतीयों में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। 'संडेज ऑन साइकिल' एक बेहद रोचक और दूरदर्शी पहल है।'

'खेल सिर्फ पदक जीतने के बारे में नहीं है; यह अनुशासन, त्याग और आकांक्षाओं को जगाने के बारे में है। हर खिलाड़ी के पीछे पूरा परिवार होता है जो त्याग करता है और उनके सपनों को साकार करने में मदद करता है। उनकी सफलता देश की सफलता बन जाती है। आज यहां भाग ले रहे बच्चों को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के कई भावी पदक विजेता हमारे बीच ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और मार्गदर्शन में, इस तरह की पहल भारतीय खेलों के भविष्य को आकार दे रही हैं,' उन्होंने आगे कहा।

देश भर में, एसएआई क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, खेलो इंडिया केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ इसी तरह के उत्सव मनाए गए, जिसमें ओलंपियन, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता और खेल जगत की हस्तियां अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों के साथ शामिल हुईं। माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने गुवाहाटी में उत्सव का नेतृत्व किया, पूर्व कुश्ती स्टार बबीता फोगाट ने धर्मशाला में भाग लिया, जबकि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम - जो प्रतिष्ठित फिल्म चक दे! इंडिया की प्रेरणाओं में से एक थीं - मुंबई में उत्सव में शामिल हुईं, जिससे खेल जनभागीदारी की राष्ट्रव्यापी भावना को बल मिला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दिसंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से, फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल भारत की सबसे बड़ी समुदाय-संचालित फिटनेस पहलों में से एक के रूप में उभरी है, जो 3.07 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंच चुकी है, 50 लाख से अधिक साइकिल चालकों को शामिल कर चुकी है और जमीनी और डिजिटल भागीदारी के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक भारतीयों से जुड़ चुकी है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ (सीएफआई), योगासन भारत, राहगिरी फाउंडेशन, एमवाई बाइक्स और एमवाई भारत के सहयोग से आयोजित यह पहल प्रधानमंत्री के "फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज" के विजन को और मजबूत करती है।

जैसे-जैसे अहमदाबाद 2030 में ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की ओर लगातार बढ़ रहा है, आज का यह उत्सव एक ऐसे राष्ट्र की सशक्त याद दिलाता है जो एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी खेल भविष्य की ओर मिलकर साइकिल चला रहा है।

पीएम मोदी की ईवी खरीदने की अपील के बीच कहीं पेट्रोल-सीएनजी कारों की बिक्री ना घट जाए, ग्राहक बड़े संवेदनशील हैं

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में ईवी को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोग सोचने पर जरूर मजबूर हो गए हैं कि अगर आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की किल्लत हो गई तो फिर क्या होगा? ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जरूरी और मजबूरी दोनों हो जाएगी। ऐसे हालात में बहस शुरू हो गई है कि क्या पीएम की ईवी अडॉप्शन की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री घट जाएगी, आइए विस्तार से जानते हैं।

(एजेंसी)।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर मोबिलिटी हैं, ये बात तो हर कोई जानना-बुझता और समझता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईवी अपनाने की अपील के बाद कठए, यानी पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कारों की बिक्री प्रभावित होगी, यह सवाल इन दिनों काफी लाजिम हो गया है। दरअसल, ईरान की इस्राइल और अमेरिका से युद्ध के बाद दुनियाभर में तेल संकट की स्थिति और गहरा गई है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार ऐसी स्थिति में काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और इस सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की तेल आयात पर निर्भरता का आने वाले समय में गंभीर परिणाम देखने के मिल सकता है।

क्या से क्या गया, देखते-देखते...

मौजूदा संकट की स्थिति के दुष्परिणाम भी बीते 10 दिनों के दौरान

दिख गए हैं, जब 3 बार पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। अब लोगों को पेट्रोल और डीजल 5 रुपये और सीएनजी 4 रुपये महंगे मिल रहे हैं। ये सारे हालात नए कार बायर्स को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इन्हें पेट्रोल-डीजल और सीएनजी पावर्ड कार खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रिक कार? लेकिन परेशानी यह भी है कि ईवी को लेकर लोगों में इतनी ज्यादा अनिश्चितता की स्थिति है कि वो इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी की ईवी अपनाने की अपील का कुछ खास असर शायद दी दिखे और पेट्रोल-सीएनजी और डीजल, हाइब्रिड कारों की बिक्री की रफ्तार पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा।

बढ़ते तेल के दाम ने उड़ाई नींद

एक बात तो सत्य है कि मौजूदा

कार बायर्स कुछ ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं और हालिया दिनों में फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी के बाद उनके फैसले प्रभावित हुए हैं। दरअसल, बाजार फिलहाल मल्टी-फ्यूल ट्रांजिशन के दौर में है। पीएम मोदी की अपील और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्वेरीज और बुकिंग में उछाल तो ला दिया है, लेकिन क्या ये सारे नंबर आखिरकार आने वाले समय में सड़कों पर दिखेंगे, ये बड़ा सवाल है।

सेकेंड कार ईवी बनने वाली है...

खास तौर पर उन परिवारों में, जिनके पास पहले से एक पेट्रोल-डीजल या सीएनजी या हाइब्रिड कार है, वे अब सेकेंड कार के तौर पर ईवी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, सीएनजी और हाइब्रिड ज्यादातर ग्राहकों के लिए पेट्रोल-डीजल के अल्टरनेटिव व्हीकल के रूप में है। हालिया आंकड़ों की मानें तो पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सीएनजी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 24 फीसदी तक पहुंच गई है। हालांकि, पेट्रोल कारें अभी भी सबसे ज्यादा बिकती हैं।

ग्राहकों के लिए विकल्प क्या?

अब बात आती है कि आखिरकार ग्राहक करे तो क्या करे? ईवी के लिए माहौल बनाने से पहले ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती विकल्पों पर जोर देना ज्यादा जरूरी है। भारतीय ग्राहक हमेशा से वैल्यू फॉर मनी चीज खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि, तेल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी ने ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव किए हैं। अब सामान्य ग्राहक केवल कार की खरीद कीमत नहीं, बल्कि उसकी रनिंग कॉस्ट को भी गहराई से देख रहे हैं। ऐसे में ईवी की कम रनिंग कॉस्ट उनके फैसले को प्रभावित करने में लगे हैं। जैसे-जैसे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और बैटरी की कीमतें कम हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा।

लखनऊ में बसपा की बैठक, मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर दिया मूलमंत्र, कहा-वोट की सुरक्षा इज्जत-आबरू, मजहब की तरह करें

जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा, कहा-सत्ता में वापस आना है

(एजेंसी)।

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को स्टेट यूनिट की बड़ी बैठक की. इसमें पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर तक की जमीनी मजबूती, विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों और पार्टी को आर्थिक सहयोग के साथ जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा की. प्रगति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश में

चुनाव जिस प्रकार की नई-नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी अधिक चुस्त-दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है. पार्टी के पक्ष में बढ़ते हुए जन रुझान से यूपी में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनेगी.

बैठक में पोलिंग बूथ स्तर के प्रमुख प्रभारियों सहित विधानसभा, जिला और स्टेट कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे. सभी ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट दी, जिसे संतोषजनक पाने के बावजूद मायावती ने यूपी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही न बरतने की हिदायत दी. कहा कि धुरंधर व जुगाड़ू विरोधियों की हर चाल का मुकाबला 2007 की तरह ही पूरी तरह से डट कर करना है. पार्टी प्रत्याशियों के चयन के बारे में बरती जा रही सावधानी जरूरी है. कुल मिलाकर, 'हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है' का मिशन यानि 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की सरकार एक बार फिर लाने के लिए पूरे जी-जान से वोट की सुरक्षा अपनी इज्जत-आबरू, जान-माल व मजहब की तरह से करनी है.

कहा कि हाल ही में सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा आमचुनाव में जो कुछ हुआ व जिस प्रकार से हुआ, उसका समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में ही या इससे थोड़ा पहले लगभग एक साथ होने वाले विधानसभा आमचुनाव में इससे सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा. खासकर सत्ताधारी पार्टी व सरकारें वादों की खानापूर्ति करने और अनेकों प्रकार की अप्रत्याशित व अभूतपूर्व तरीके से चुनाव को प्रभावित करने में सफल हो जाती हैं. उसके बाद जनहितैषी गवरनेन्स के बजाय ज्यादातर ध्यान भटकाने वाले कार्यकलापों के कारण फिर जनता अपने आपको काफी ठगा हुआ महसूस करने लगती है. उसका क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत?

उन्होंने कहा कि बीएसपी की कैडर बैठकों में लोगों को इस कटु अनुभवों से अवगत करना जरूरी है कि सरकारें व पार्टियां चुनाव के समय जनहितैषी व जनकल्याणकारी होने का ढिंढोरा पीटती हैं और उसमें धन लुटाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वे अपने वादों, घोषणाओं व दावों के प्रति उतना ही उदासीन हो जाती हैं. यही कारण है कि इन पार्टियों की छलावापूर्ण व विभाजनकारी राजनीति से देश व जनहित का सही से भला नहीं हो रहा है, उनका जीवन लगातार लाचार व मजबूर बना हुआ है. ऐसी छलावा/वादाखिलाफी के विरुद्ध जनता को जागरुक होना होगा, जो उनके वोट के अधिकार का संदेश और सीख भी है. उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों की ऐसी छलावापूर्ण राजनीति का दुष्परिणाम यह भी है कि चुनाव के समय उन्हें हर प्रकार से लुभाया जाता है लेकिन चनाव के बाद महंगाई, बेरोजगार व नये-नये नियम-कानून के जरिये हर प्रकार के तनाव सहित उनके जीवन के जंजाल को और भी बढ़ा दिया जाता है.

केशव प्रसाद मौर्य ने 32 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, मिलेंगी स्थानीय नागरिकों को सुविधाएं

(एजेंसी)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मोहनलालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग द्वारा निर्मित 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये है। इन विकास कार्यों में सी.सी. रोड निर्माण, खड़ंजा निर्माण व मरम्मत, इंटरलॉकिंग, नाला-नाली निर्माण, आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापना, तालाब निर्माण और पंचायत भवनों के साथ-साथ विकासखण्ड परिसर के भवनों की मरम्मत व पुताई का काम शामिल है।

यह परियोजनाएं मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सिसेंडी, दयालपुर, हसनपुर, रायभान खेड़ा, परसपुरठ्ठा, गौतम खेड़ा, नन्दौली, सलेमपुर अचाका, रघुनाथ खेड़ा, धतौनी, डलौना, उतरावां और कुशमौरा में

क्रियान्वित की गई हैं। इन कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।

डबल इंजन सरकार का मिलेगा लाभ

लोकार्पण के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, पेयजल और बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जलदूत ऐप' से होगा प्री-मानसून भूजल स्तर का सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता की स्थिति जांचने, जलस्तर में गिरावट को रोकने और संभावित जल संकट की पहचान के लिए उच्च अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्री-मानसून 2026 के अंतर्गत भूजल स्तर का आकलन "जलदूत ऐप" के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, यह विशेष अभियान 25 मई से 15 जून 2026 तक संचालित होगा।

इस अभियान के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों (श्रम रोजगार) को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित कुओं का भूजल स्तर वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप मापा जाए और आंकड़े जलदूत ऐप पर अपलोड किए जाएं। मापन के दौरान मेजरिंग टेप का उपयोग और फोटो प्रलेखन अनिवार्य होगा, साथ ही एक ग्राम पंचायत के सभी कुओं का डेटा एक ही दिन में संकलित किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि ऐप के माध्यम से एकत्र आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण संरचनाओं की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन और संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

'मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूं', लालू के बेटे तेज प्रताप निकले योगी आदित्यनाथ के फैन

(एजेंसी)।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार वापस होगी।

'मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं।'

पटना/विंध्याचलः 'मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा (तीसरी बार) सरकार यहां (उत्तर प्रदेश) बनाने का काम करेंगे।' दरअसल, बिहार की सियासत के सबसे चर्चित चेहरों में से एक तेज प्रताप यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के धार्मिक दौरों पर हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और मिजार्पुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति गरमा गई।

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने अपने सगे रिश्तेदार अखिलेश यादव को सीधे

तौर पर नकार दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर सबको चौंका दिया।

विंध्याचल में तेज प्रताप यादव ने कहा, 'देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। जहां तक बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा, किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्म किया। हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में। या तो हार होती है या फिर जीत। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा (तीसरी बार) सरकार यहां (उत्तर प्रदेश) बनाने का काम करेंगे।'

दरअसल, तेज प्रताप आजकल उत्तर प्रदेश के तीर्थाटन पर हैं। पहले वो वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किए। फिर वो विंध्यावासिनी मां का दर्शन-पूजन के लिए विंध्याचल पहुंचे। वहां तेज प्रताप पत्रकारों से टकरा गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के परफॉर्मेंस और चुनावी रिजल्ट पर सवाल कर दिया। इसके बाद सीधे-सीधे तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को नकार दिया। वैसे, तेज प्रताप के अखिलेश यादव से निजी रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों रिश्तेदार भी लगते हैं। मगर, तेज प्रताप के दिल पर फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं। इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा (तीसरी बार) सरकार यहां (उत्तर प्रदेश) बनाने का काम करेंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर इसका फोटो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, भगवान महादेव की पावन नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं, तेज प्रताप यादव अपने माता-पिता के सुख और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, अपने भाई-बहनों के लिए मंगलकामना की और पूरे समाज के लोगों के सुख-शांति के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा।'

'ये कोई मजाक नहीं', प्रशांत किशोर ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर सरकार को क्यों चेताया? सीजेआई को भी दे डाली सलाह!

(एजेंसी)।

देश में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' अब केवल एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं रह गई है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। लाखों-करोड़ों युवा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और अब इस मुद्दे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी खुलकर अपनी राय रखी है।

पीके ने कहा कि सरकार और व्यवस्था चला रहे लोगों को इस डिजिटल कैंपेन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भीतर बढ़ते गुस्से और निराशा का संकेत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं ने युवाओं के भीतर असंतोष पैदा किया है, जो अब सोशल

मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठाए।

दरअसल, 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम की शुरूआत उस समय चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरोप लगा कि उन्होंने वकीलों और युवाओं के संदर्भ में 'कॉकरोच' और 'परजीवी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कई बार अदालतों में ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो जाती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को शब्दों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

तकनीक से सीमा सुरक्षा हो रही सुदृढ़

उन्नत तकनीक से सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से आयोजित वार्षिक रुस्तम जी व्याख्यानमाला के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार तकनीक, ड्रोन, राडार और स्मार्ट वैमरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर एक मजबूत सुरक्षा जाल तैयार करेगी। दरअसल भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से 6000 किमी से ज्यादा लम्बी सीमा है जहां से घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर तो ज्यादातर क्षेत्रों की बाड़बन्दी हो चुकी है लेकिन पाक आतंकी तार के नीचे से लम्बी सुरंग बनाकर भारत की सीमा में घुस जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेश से लगी 4096 किमी की सीमा में जंगलों के रास्ते घुसपैठिए घुसपैठ कर असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में घुस आते हैं। इस तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ह्यस्मार्ट बार्डर ग्रिडह्न परियोजना का प्रस्ताव किया जो वर्तमान में चल रही ह्यव्यापक एकीवृत बार्डर प्रबंधन प्रणालीह्न यानि सीआईबीएमएस प्रणाली पर आधारित हो सकता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी नागरिक भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं उनकी पहले से ही भारत के अन्दर किसी निजी एजेंसी या अवैध गिरोह से संपर्क होता है। ऐसे गिरोह भारत के अन्दर प्रवेश कराने फजी राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर उन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना ठिकाना बनाने की भी सुविधा मिल जाया करती थी। असम में सीमा की निगरानी में बीएसएफ लगी है। इसके द्वारा निगरानी की सीआईबीएमएस योजना को लागू करने में राज्य सरकार ने पूरा सहयोग किया किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को लागू होने ही नहीं दिया। अब नई सरकार इस परियोजना को पूरी तरह लागू करने के लिए वृतसंकल्प है। पाकिस्तान से लगी 3323 किमी सीमा पर यह प्रणाली गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू–कश्मीर से लगती सीमा पर पूरी तरह लागू है। इन सभी राज्यों में सरकार किसी भी पाटी की हो राज्य सरकारों से बीएसएफ को पूरा सहयोग मिलता है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने के लिए बहुत सारे निजी कारोबारी सव्रिय हैं और वे अपनी फीस वसूल कर घुसपैठियों को भारत में भेजते रहे हैं। किन्तु जबसे उन्हें पता चला है कि बाड़ लगे तारों में बिजली का सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है, ये घुसपैठ गैंग परेशान है। उन्हें अपना व्यवसाय डूबता हुआ नजर आ रहा है। मजे की बात तो यह है कि पाक के घुसपैठिए भारत में हिंसा पैलाने के लिए आते हैं जिन्हें सैन्य खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर वहां के आतंकी संगठन भेजते हैं और इसके लिए पूरा खर्च वे आईएसआई और केन्द्र सरकार से वसूलते हैं। जब कि बांग्लादेश के घुसपैठिए रोजी–रोटी कमाने के लिए भारत के सीमा में घुसते हैं। भारत के अन्दर तमाम संगठन ऐसा मानते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले जरूरतमंद लोग यदि भारतीय क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के दृष्टिकोण भारत के नागरिकों के हितों के सर्वथा प्रतिवूल हैं। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ का दबाव हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही घातक साबित हुआ है। यही नहीं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के शहरों में लूटपाट, डवैती, हिंसा जैसे अपराधों में वृद्धि करते हैं। यह भी सच है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जनसंख्या विस्फोट के लिए भी वुख्यात हैं। बहरहाल अब यदि सरकार नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से घुसपैठ को रोकने की तरकीब विकसित कर रही है तो निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी इस गतिविधि पर रोक लगाई जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने जरूरत के मुताबिक नक्सलियों के संहार के लिए जो भी सिस्टम विकसित किया उसका लाभ सीआरपीएफ के जवानों को मिला और उन्होंने नक्सल को समाप्त या बहुत हद तक नियंत्रित कर दिया है। इसी तरह यदि घुसपैठ नियंत्रण के लिए गृहमंत्री की परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू कर दी गईं तो निश्चित रूप से घुसपैठ करने वाले चाहे पाकिस्तानी हों या फिर बांग्लादेश के, हजार बार सोचेंगे।

क्या पीएम मोदी की एक आवाज पर भारतीयों ने रोक दी फॉरेन ट्रिप? चौंकाने वाले हैं RBI के ये आंकड़े

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से विदेशी यात्राओं और गैर जरूरी खर्चों में संयम बरतने की अपील की थी. अब आरबीआई के ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारतीयों ने विदेश यात्रा पर खर्च पहले से ही कम करना शुरू कर दिया था. मार्च 2026 में विदेश यात्रा पर भारतीयों का खर्च घटकर 1.09 अरब डॉलर रह गया, जो जनवरी में 1.65 अरब डॉलर था. लगातार तीन महीनों की गिरावट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीयों ने फॉरेन ट्रिप्स पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है.

भारतीयों ने पीएम मोदी की अपील से पहले ही विदेश यात्रा पर खर्च कम करना शुरू कर दिया था.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का असर भारतीयों की फॉरेन ट्रिप्स पर दिखने लगा है? भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं. विदेश यात्रा पर भारतीयों का खर्च लगातार घट रहा है और मार्च 2026 में यह कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई के पहले पखवाड़े में देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से गैर जरूरी आयात, सोने की खरीद और विदेशी यात्राओं में संयम बरतने की बात कही थी, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे. दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीयों ने पीएम मोदी की अपील से पहले ही विदेश यात्रा पर खर्च कम करना शुरू कर दिया था.

आरबीआई के मुताबिक, मार्च 2026 में भारतीयों ने विदेश यात्रा पर सिर्फ 1.09 अरब डॉलर खर्च किए. फरवरी में यह आंकड़ा 1.30 अरब डॉलर था, जबकि जनवरी में विदेश यात्रा पर खर्च 1.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. यानी सिर्फ दो महीनों में विदेश यात्रा पर खर्च करीब 56 करोड़ डॉलर घट गया. यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब पश्चिम एशिया तनाव, महंगा डॉलर, बढ़ते एयरफेयर और वैश्विक अनिश्चितता ने विदेशी ट्रैवल को पहले से ज्यादा महंगा बना दिया है.

आरबीआई के लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस डेटा के मुताबिक, 'अन्य यात्रा' श्रेणी में मार्च के दौरान 62.30 करोड़ डॉलर खर्च किए गए. इसमें छुट्टियां, इंटरनेशनल होटल बुकिंग और विदेशी क्रेडिट कार्ड खर्च शामिल हैं. यह कुल यात्रा खर्च का करीब 57 प्रतिशत हिस्सा रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी ट्रिप्स पर घटती बुकिंग और नियंत्रित खर्च का असर इस डेटा में साफ दिख रहा है.

विदेश पढ़ाई और प्रॉपर्टी खरीद भी धीमी

विदेश में पढ़ाई से जुड़े खर्च में भी नरमी देखने को मिली. मार्च में 'विदेश में अध्ययन' श्रेणी के तहत खर्च घटकर 15.17 करोड़ डॉलर रह गया. जनवरी में यही आंकड़ा 26.74 करोड़ डॉलर था. विदेश में प्रॉपर्टी खरीद पर भारतीयों का खर्च भी घटा है. मार्च में सिर्फ 3.86 करोड़ डॉलर विदेश में अचल संपत्ति खरीद पर खर्च किए गए, जबकि फरवरी में यह 5.13 करोड़ डॉलर था.

आखिर क्यों कम हो रही हैं फॉरेन ट्रिप्स

विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हैं. पहली वजह पश्चिम एशिया तनाव और वैश्विक अनिश्चितता है, जिससे लोग महंगी विदेशी यात्राओं से बच रहे हैं. दूसरी वजह डॉलर की मजबूती है. रुपये की कमजोरी के कारण विदेश यात्रा पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है. तीसरी वजह सरकार का विदेशी मुद्रा बचाने पर बढ़ता फोकस है. सरकार लगातार लोकल खर्च, घरेलू पर्यटन और आयात पर निर्भरता घटाने पर जोर दे रही है.

क्या है एलआरएस योजना

आरबीआई की एलआरएस योजना के तहत भारत का कोई भी निवासी एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है. यह रकम यात्रा, पढ़ाई, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद या अन्य वैध खर्चों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. मार्च 2026 में एलआरएस के तहत कुल 2.59 अरब डॉलर विदेश भेजे गए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यात्रा खर्च का था.

विदेशी मुद्रा बचाने पर सरकार का जोर

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है. ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में वैश्विक तनाव और महंगा डॉलर बना रहता है, तो भारतीयों की विदेशी यात्राओं और बाहरी खर्च में और कमी देखने को मिल सकती है.

पीएम मोदी के साथ वायरल हुए वे दो 'नन्हें दोस्त' कौन हैं? मिल गया जवाब

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर दो प्यारे बच्चों के साथ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों के साथ कोई तस्वीर आती है, तो वह तुरंत वायरल हो जाती है. शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दो बेहद प्यारे बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."

इन तस्वीरों में एक गुलाबी फ्रॉक पहनी नन्ही बच्ची और एक छोटा बालक पीएम मोदी के साथ उनके आधिकारिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' (पीएमओ) में खेलते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में पीएम मोदी बच्चे को गोद में उठाकर नोटबुक दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में बच्चे उनकी डेस्क के पास खड़े हैं. इन तस्वीरों के सामने आते ही हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पीएम मोदी के ये दो 'नन्हें दोस्त' हैं कौन?

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से उठा सस्पेंस से पर्दा

इस सस्पेंस पर से पर्दा तब उठा जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी (TDP) सांसद राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने परिवार की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों को ध्यान से देखते ही साफ हो गया कि पीएम मोदी के साथ वायरल हो रहे वे दो नन्हें बच्चे कोई और नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के ही बच्चे हैं.

राम मोहन नायडू अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे. इस मुलाकात के दौरान वहां एक बेहद भावुक और यादगार नजारा देखने को मिला, जहां परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ प्रधानमंत्री से आशीर्वाद ले रही थीं.

मां ने सौंपा पौधा और मंत्री ने जताया आभार

इस खास मुलाकात की एक और बड़ी विशेषता यह रही कि राम मोहन नायडू की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बेहद लोकप्रिय अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत एक हरा–भरा पौधा भेंट किया. तस्वीरों में प्रधानमंत्री पूरे परिवार के साथ बेहद गर्मजोशी से मिलते, बातचीत करते और हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मुलाकात को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा उनके परिवार की तीन पीढ़ियों तक जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालने और बच्चों व परिवार को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया.

लाल किले से गूंजा संदेश, सीएम विष्णुदेव बोले- दुनिया को प्रकृति संग जीना जनजातीय समाज से सीखना होगा

(जीएनएस)।

देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रविवार को जनजातीय संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का ऐसा विराट दृश्य देखने को मिला, जिसने पूरे माहौल को सांस्कृतिक ऊर्जा से भर दिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में देशभर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और पारंपरिक समुदायों के लोग एक मंच पर जुटे।

जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास राजनीतिक और सामाजिक महत्व दिया।

लाल किले में दिखा जनजातीय भारत का रंग

लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब मांदर, ढोल और पारंपरिक लोकधुनों की आवाज गूंजी तो पूरा मैदान जनजातीय संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया।

अलग–अलग राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत के जरिए भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की झलक पेश की। पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम बनकर नहीं रहा, बल्कि जनजातीय अस्मिता और पहचान के राष्ट्रीय संदेश के रूप में सामने आया।

'प्रकृति के साथ विकास' का मॉडल दे सकता है जनजातीय समाज

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज सिर्फ जंगलों का रक्षक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन

और जीवंत रूप है। उन्होंने कहा कि सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए जनजातीय समाज ने प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखा है।

आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब जनजातीय जीवनशैली दुनिया को टिकाऊ विकास का रास्ता दिखा सकती है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से जुड़ी है। राज्य में 42 प्रकार की जनजातियां रहती हैं और लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है।

बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह का किया स्मरण

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इन महानायकों ने अपने अधिकार, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष और बलिदान का इतिहास रचा।

जनजातीय भाषा और संस्कृति बचाने पर जोर

विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने 'आदि परब', 'बस्तर पंडुम' और 'बस्तर ओलंपिक' जैसे आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय प्रतिभा और पहचान को राष्ट्रीय मंच देने की पहल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समाज की संस्कृति उसकी भाषा से जीवित रहती है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी जनजातीय भाषाओं में बच्चों को शुरूआती शिक्षा देने पर काम कर रही है, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे।

रळ सूची और आरक्षण पर भी उठाया बड़ा मुद्दा

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों और पहचान से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर यह मांग लगातार मजबूत हो रही है कि जो लोग अपनी मूल जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और धर्म को छोड़ चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर किए जाने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

साय ने कहा कि इससे आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उन समुदायों तक पहुंचेगा जो आज भी अपनी मूल परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बचाकर रखे हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि यह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है। दिनभर चले इस आयोजन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जनजातीय समाज सिर्फ भारत के अतीत की पहचान नहीं, बल्कि भविष्य के टिकाऊ विकास और सांस्कृतिक संतुलन की भी मजबूत नींव है।

45 डिग्री का टॉर्चर! आपकी हरी-भरी फसलों को न लगे लू की नजर

(जीएनएस)।

देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी और लू ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते तापमान का असर अब खेतों में साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में मिट्टी तेजी से सूख रही है, सब्जियों की फसल झुलसने लगी है और नई पौध कमजोर पड़ रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी सामान्य मौसम से काफी अलग है, इसलिए किसानों को भी अब खेती के तरीके बदलने होंगे।

केवल सिंचाई करना काफी नहीं होगा, बल्कि खेत की नमी बचाने, पौधों को तेज धूप से बचाने और सही पोषण देने पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार

पहुंच चुका है, जिससे फसलों के साथ भूजल स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

सबसे ज्यादा खतरे में कौन सी फसलें?

भीषण गर्मी का असर सबसे ज्यादा सब्जियों, नर्सरी और हरी पत्तेदार फसलों पर पड़ रहा है। टमाटर, पालक, धनिया, मिर्च, ब्रोकली, फूलगोभी और नई पौध तेज धूप में जल्दी सूखने लगती है। कई जगहों पर पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधों में फूल बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

फल वाली फसलों पर भी गर्मी का असर दिखने लगा है। आम, तरबूज, खरबूज और अंगूर जैसी फसलों में समय से पहले फल गिरने की समस्या बढ़ सकती है। अधिक तापमान के कारण फलों का आकार छोटा रह जाता है और गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

बदलते मौसम में बदलना होगा सिंचाई का तरीका

गर्मी में खेतों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन पारंपरिक सिंचाई में पानी की काफी बबार्दी होती है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

इन तकनीकों में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इससे कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाती है और बिजली का खर्च भी कम होता है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर से होंगे ये फायदे

कम पानी में बेहतर सिंचाई

जड़ों तक लगातार नमी पहुंचती है

तेज गर्मी में भी पौधे हरे रहते हैं

मजदूरी और बिजली खर्च कम होता है

फसल की बढ़वार तेज होती है

मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है

मल्चिंग तकनीक से बच सकती है फसल

कृषि विभाग के अनुसार, इस मौसम में मल्चिंग तकनीक किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती

होर्मुज स्ट्रेट से हटेगी नाकेबंदी! अमेरिका-ईरान डील पर आई वो 'अच्छी खबर', जिसका पूरी दुनिया को था इंतजार

(जीएनएस)।

मध्य पूर्व में कई महीनों से जारी तनाव के बीच अब राहत की उम्मीद दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते और होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुलने के संकेतों ने दुनिया को बड़ी राहत दी है। ईरान ने दावा किया है कि अगले 30 दिनों में होर्मुज से जहाजों की आवाजाही युद्ध से पहले जैसी हो जाएगी।

इस रास्ते के बंद होने से भारत समेत कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई थी। अब अगर समझौता होता है तो पेट्रोल–डीजल की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा संकट पर बड़ा असर पड़ सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट खुलने से दुनिया को राहत

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल और गैस दुनिया तक पहुंचाता है। युद्ध शुरू होने के बाद यहां जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। इससे एशिया और यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा गया। अब ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगले एक महीने में स्थिति सामान्य हो सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आने की उम्मीद बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें; वर क्श्ल्ल ढ्ढूी ॐ': होर्मुज खुलेगा, यूरेनियम जाएगा! अमेरिका–ईरान के बीच तैयार हुए टडव के 5 सबसे बड़े राज

अमेरिका–ईरान समझौते के करीब

अमेरिकी विदेश मंत्री टं१ूङ्क फ्छुङ्क ने भारत दौरे के दौरान कहा कि जल्द ही दुनिया को अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ऊङ्मल्लं' ळ१४स्र ने भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच शत्रुता खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर सहमति बन चुकी है। फिलहाल समझौते की अंतिम शर्तों पर बातचीत जारी है।

भारत समेत कई देशों पर पड़ा असर

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा जो खाड़ी देशों से तेल और गैस खरीदते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई एशियाई देशों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ीं और कई जगह गैस की कमी भी देखने को मिली। भारत के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद अहम है क्योंकि देश की बड़ी तेल जरूरतें इसी मार्ग से पूरी होती हैं। अब रास्ता खुलने की खबर से आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

पाकिस्तान निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख अ३े ट४ल्ल१ ने हाल ही में तेहरान जाकर ईरानी नेताओं से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी ईरान जा चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर को स्थायी बनाने और युद्ध खत्म कराने में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है।

तेल प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा

ईरानी मीडिया के मुताबिक संभावित समझौते में अमेरिका की ओर से ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों को हटाने पर भी चर्चा हुई है। अगर ऐसा होता है तो ईरान दोबारा बड़ी मात्रा में तेल निर्यात कर सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। हालांकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी कोई बड़ा समझौता स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अंतिम समझौते से पहले कई मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी माना जा रहा है।

ताला और तालीम के बाद अब 'खेलों का हब' बनेगा अलीगढ़, ₹57 करोड़ के हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देंगे सीएम योगी, जानें क्या है खास

उत्तर प्रदेश में खेल क्रांति को नई गति देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही अलीगढ़ में बने भव्य इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे. 13,000 स्क्वायर मीटर में फैला यह परिसर ₹57 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है. इसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल बैडमिंटन-बास्केटबॉल कोर्ट और हाईटेक जिम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं, जिससे अब पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों को दिल्ली-नोएडा नहीं भागना पड़ेगा. यह परिसर प्रतिभावान युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश को 'खेल प्रदेश' बनाने के अपने संकल्प को तेजी से जमीन पर उतार रही है. इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर अलीगढ़ मंडल के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी है. अलीगढ़ में 13,000 स्क्वायर मीटर के विशाल दायरे में फैला, 57 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना ओलंपिक स्टैंडर्ड इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस अत्याधुनिक और भव्य खेल परिसर का उद्घाटन कर इसे जनता और प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित करने जा रहे हैं.

यह हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ अलीगढ़, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए नए अवसरों का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. अब छोटे कस्बों और गांवों के बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए विश्वस्तरीय मंच मिलेगा.

अब दिल्ली-नोएडा भागने की जरूरत नहीं

अलीगढ़ के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अलीगढ़ मंडल का पहला ऐसा विश्वस्तरीय इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसे पूरी तरह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने

कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के शुरू हो जाने के बाद अलीगढ़ और इसके आसपास के जिलों जैसे हाथरस, कासगंज और एटा के खिलाड़ियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या लखनऊ जैसे बड़े और महंगे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. अब स्थानीय स्तर पर ही खिलाड़ियों को वह सब कुछ मिलेगा जो किसी इंटरनेशनल एकेडमी में मिलता है. इससे सबसे ज्यादा फायदा उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन देश के लिए मेडल जीतने का दम रखते हैं.

इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

इस विशाल खेल परिसर को बेहद आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर खिलाड़ियों को क्या-क्या वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने जा रही हैं:

ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल: इस कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है. अत्याधुनिक फिल्टरेशन और हीटिंग सिस्टम से लैस यह पूल भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं का मुख्य केंद्र बनेगा. अलीगढ़ के तैराकों को अब अपनी ही धरती पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का अभ्यास करने का मौका मिलेगा.

इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्ट: परिसर के अंदर एक बड़ा मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है. इसमें बैडमिंटन और बास्केटबॉल के कोर्ट्स को हूबहू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को सीधे बड़े टूनामेंट्स जैसा अनुभव मिल सके.

हाईटेक जिम और बिलियर्ड्स रूम: खिलाड़ियों की फिटनेस को निखारने के लिए यहां एक अत्याधुनिक जिम बनाया गया है, जहां प्रोफेशनल ट्रेनर्स की देखरेख में खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे. इसके अलावा इनडोर गेम्स के शौकीनों के लिए एक शानदार बिलियर्ड्स रूम भी तैयार किया गया है.

सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि बनेगा 'स्पोर्ट्स हब'

योगी सरकार की योजना इस परिसर को सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े 'स्पोर्ट्स हब' के रूप में विकसित किया गया है. यहां बड़े-बड़े टूनामेंट्स को आसानी से आयोजित कराने के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं:

अत्याधुनिक स्पेक्टेटर गैलरी: मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए एक बड़ी और आरामदायक गैलरी बनाई गई है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर मुकाबलों का रोमांच उठा सकेंगे.

श्क्ढ रूम और मीडिया सेंटर: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पेशल वीआईपी रूम, आधुनिक लाउंज एरिया और एक पूरी तरह से सुसज्जित मीडिया रूम भी बनाया गया है. यानी आने वाले समय में अलीगढ़ देश के बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

बदलेगी अलीगढ़ की पहचान, सपनों को मिलेगी नई उड़ान

सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है. सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है गांवों में मिनी स्टेडियम बनाना, जिलों में हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करना और ग्रामीण अंचलों के युवाओं को सीधे खेलों की मुख्यधारा से जोड़ना. अलीगढ़ का यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसी दूरदर्शी विजन का एक चमकता हुआ उदाहरण है. इस कॉम्प्लेक्स के तैयार होने से अलीगढ़ के स्थानीय नागरिकों, खेल प्रेमियों और युवा एथलीटों में जबरदस्त उत्साह है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट अलीगढ़ के इतिहास में एक 'गेम चेंजर' साबित होने वाला है. जिस अलीगढ़ को दुनिया अब तक सिर्फ उसके मशहूर ताला उद्योग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए जानती थी, अब वही अलीगढ़ खेल जगत के नए पावरहाउस और चमकते हुए सितारों के केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा. स्थानीय खिलाड़ियों का भी कहना है कि इस तरह की सुविधाएं मिलने से अब उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी और वो दिन दूर नहीं जब अलीगढ़ के खिलाड़ी ओलंपिक के मंच पर तिरंगा लहराएंगे.

यूपी की ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर नई रफ्तार, सीएम योगी के नेतृत्व में 'डिफेंस कॉरिडोर' की ताकत दिखाएगा उत्तर प्रदेश

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। राज्य में रक्षा निर्माण और एयरोस्पेस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर चमकाने के लिए राजधानी लखनऊ में 'उत्तर प्रदेश रक्षा और एफडीआई कॉन्क्लेव-2026' का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) में भारी विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना, औद्योगिक विस्तार को गति देना और रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के बीच एक मजबूत समन्वय तंत्र तैयार करना है।

वैश्विक दिग्गजों का लगेगा मेला, यूपी दिखाएगा अपनी ताकत

इस महामंच पर उत्तर प्रदेश अपनी अत्याधुनिक रक्षा निर्माण क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का लोहा मनवाएगा। कॉन्क्लेव में राज्य के मजबूत एक्सप्रेसवे नेटवर्क, रणनीतिक लोकेशन, विशाल औद्योगिक भूमि बैंक, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और चाक-चौबंद कानून व्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के सामने सबसे बड़े 'यूएसपी' (वरढ) के रूप में पेश किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी के साथ कई

महत्वपूर्ण सत्र होंगे, जिनमें 'डिफेंस और एयरोस्पेस इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश क्यों?' और 'यूपी एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024' जैसे नीतिगत विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा।

सीएम योगी का विजन और सीधा संवाद

प्रस्तावित एजेंडे के अनुसार, भारत सरकार के रक्षा उत्पादन सचिव इस कॉन्क्लेव में देश के रक्षा क्षेत्र के भविष्य का रोडमैप और मार्गदर्शन साझा करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने की अपनी दूरगामी रणनीति को दुनिया के सामने रखेंगे। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ होने वाले बी2बी (Business-to-Business) और बी2जी (Business-to-Government) इंटरैक्शन होंगे, जो उद्योग जगत और सरकार के नीति-निर्धारकों के बीच सीधे संवाद और ऑन-द-स्पॉट फैसिलिटेशन का रास्ता साफ करेंगे।

टाटा, बोइंग और स्काईरूट जैसी कंपनियां होंगी शामिल

डिफेंस सेक्टर में यूपी की इस बड़ी हुंकार का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश की शीर्ष कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एचएएल (ऌअछ), बीईएल (इएछ) के साथ-साथ निजी क्षेत्र की दिग्गज टाटा, अडानी, बोइंग, एयरबस और लॉकहीड मार्टिन शामिल हैं। इनके अलावा डीआरडीओ (ऊफऊड) जैसी शीर्ष एजेंसियां और एमएसएमई (टरटए) सेक्टर की अग्रणी ताकतें जैसे स्काईरूट और आइडियाफोर्ज भी इस महामंथन में सहभागिता करेंगी, जिससे स्टार्टअप्स को भी नया पंख मिलेगा।

निवेश, रोजगार और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना होगा साकार

इस कॉन्क्लेव से उत्तर प्रदेश को आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर कई बड़े परिणाम मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारी-भरकम निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (टङ्गव२) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा कॉरिडोर में ही इंटरनेशनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी काम होगा। योगी सरकार पहले ही डिफेंस कॉरिडोर को राज्य की 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मुख्य आधार घोषित कर चुकी है। ऐसे में यह कॉन्क्लेव प्रदेश के युवाओं के लिए हाई-टेक रोजगार और उत्तर प्रदेश में रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए युग का सूत्रपात साबित होने वाला है।

लखनऊ मेट्रो का मेगा विस्तार: 10 नए कॉरिडोर से बाराबंकी तक पहुंचेगी रफ्तार, 150 किमी. तक होगा विस्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो आने वाले 10 वर्षों में राजधानी के दायरे से निकलकर आसपास के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने जा रही है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो नेटवर्क का करीब 150 किलोमीटर तक विस्तार प्रस्तावित है, जिसके तहत 7 से 10 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इस विस्तार योजना के तहत लखनऊ के अधिकतर हिस्सों के साथ-साथ बाराबंकी तक मेट्रो कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। यूपीएमआरसी ने सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और अब जल्द ही इन कॉरिडोर का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराया जाएगा।

सर्वे रिपोर्ट के बाद शासन को भेजा गया प्रस्ताव

शासन के निर्देश पर यूपीएमआरसी ने मेट्रो विस्तार की कार्ययोजना तैयार करने के लिए शहर के प्रमुख रूटों का विस्तृत सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट शुक्रवार को शासन को भेज दी गई है। रिपोर्ट में विभिन्न रूटों पर 7 से 10 कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा

गया है, जो कुल मिलाकर करीब 150 किलोमीटर तक फैले होंगे।

सूत्रों के अनुसार, शासन ने यूपीएमआरसी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इन प्रस्तावित कॉरिडोर का डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

जहां ज्यादा यात्री, वहां पहले बनेगी मेट्रो

यूपीएमआरसी ने सेकंड फेज के बाद जिन 10 कॉरिडोर को प्राथमिकता पर तैयार किया है, उनका चयन फिजिबिलिटी और संभावित यात्री संख्या के आधार पर किया गया है। सर्वे में यह आकलन किया गया कि मेट्रो शुरू होने के बाद किस रूट पर सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होगी।

इसी प्राथमिकता के आधार पर अयोध्या रोड और चारबाग से पीजीआई तक का रूट सबसे अधिक व्यस्त और व्यवहारिक पाया गया है। यही वजह है कि इन कॉरिडोर को शुरूआती चरण में प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

बाराबंकी तक पहुंचेगी मेट्रो कनेक्टिविटी

प्रस्ताव के अनुसार, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक चलने वाली मौजूदा मेट्रो लाइन को अयोध्या रोड स्थित पॉलिटेक्निक चौराहा, कमता चौराहा, मटियारी और अनौराकला होते हुए बाराबंकी तक जोड़ने की योजना है। इससे राजधानी लखनऊ और बाराबंकी के बीच यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह विस्तार न सिर्फ शहरी कनेक्टिविटी मजबूत करेगा, बल्कि आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा।

इकाना स्टेडियम, पीजीआई और राजाजीपुरम जैसे इलाकों पर फोकस

यूपीएमआरसी की रिपोर्ट में इकाना स्टेडियम, तेलीबाग, पीजीआई, राजाजीपुरम, आईआईएम रोड और आसपास के इलाकों में भी मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव शामिल है। इन क्षेत्रों में आबादी और यात्री संख्या को देखते हुए इन्हें संभावित प्राथमिक रूट के तौर पर चिह्नित किया गया है।

इससे शहर के उन हिस्सों को भी मेट्रो सुविधा मिल सकेगी, जहां अभी सार्वजनिक परिवहन का दबाव ज्यादा है।

मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग और ई-व्हीकल सुविधा का प्रस्ताव

डीपीआर में मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही हर स्टेशन पर ई-साइकिल, ई-बाइक और अन्य ई-व्हीकल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, ताकि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत की जा सके।

अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई पर DM-ADM लखनऊ पर जुमार्ना, वकील की शिकायत पर बिना अधिकार दर्ज किया था केस

(जीएनएस)।

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने पर जिलाधिकारी लखनऊ और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुमार्ना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के कार्यवाही कर याची को अनावश्यक रूप से परेशान किया।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश निवास कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने एडीएम (न्यायिक) द्वारा 10 मार्च को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कंपनी को विवादित भूमि बेचने और निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि एक अधिवक्ता आर पी सिंह, जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था, ने पहले कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा और बाद में जिलाधिकारी के

समक्ष शिकायत दाखिल कर दी।

चंडीगढ़ में दूसरी मंजिल की छत से गिरी लड़की; गली से गुजर रहे

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भूमि का हस्तांतरण अवैध तरीके से हुआ है और उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिकायत को सीधे दर्ज कर एडीएम (न्यायिक) को भेज दिया, जिन्होंने अंतरिम आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 104 और 105 के तहत कार्यवाही केवल उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा ही शुरू की जा सकती है।

नियम 103 के अनुसार पहले लेखपाल की रिपोर्ट और फिर एसडीएम द्वारा पक्षकारों को नोटिस देकर सुनवाई आवश्यक है, लेकिन इस मामले में पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया।पीठ ने टिप्पणी की कि संबंधित अधिवक्ता ने अपने विधिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए याची को डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया।

कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने बिना अधिकार क्षेत्र के मामला दर्ज किया जबकि एडीएम (न्यायिक) ने बिना विधिक संतोष और बिना आवेदन आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने पूरी कार्यवाही और एडीएम (न्यायिक) का आदेश रद करते हुए निर्देश दिया कि जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) दोनों छह सप्ताह के भीतर अपने व्यक्तिगत खातों से 20-20 हजार रुपये की लागत अदा करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि सरकारी कोष से नहीं दी जाएगी।

एलन मस्क को चीनी जासूस ने वेटर बन कर कराया डिनर, बीजिंग से आई फोटो से टेंशन में ट्रंप

(जीएनएस)।

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के चीन दौरे से जुड़ा एक नया दावा सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में हुए स्टेट डिनर के दौरान मस्क के पीछे खड़ी वेट्रेस कोई आम सर्वर नहीं बल्कि चीन की सेना ढछअ की सीनियर अधिकारी मेजर चेंग चेंग थीं।

चीन विरोधी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने फोटो शेयर कर इसे "संभावित जासूसी एंगल" बताया है। हालांकि इन दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे चीन की कथित खुफिया रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।

आखिर क्या है पूरा विवाद?

पूरा विवाद उस तस्वीर से शुरू हुआ जिसमें बीजिंग के स्टेट डिनर में एलन मस्क के पीछे एक महिला वेट्रेस खड़ी दिखाई दी। चीन विरोधी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने दावा किया कि यह महिला असल में ढछअ की अधिकारी मेजर चेंग चेंग हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी सैन्य तस्वीरें भी शेयर कीं और कहा कि दोनों महिलाएं एक ही हैं। जेंग ने यहां तक आरोप लगा दिया कि महिला ने वर्दी के नीचे "कुछ छिपा" रखा हो सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई।

कौन हैं मेजर चेंग चेंग?

चेंग चेंग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी ढछअ का जाना-पहचाना चेहरा मानी जाती हैं। वे चीन की पहली महिला ऑनर गार्ड कमांडर के रूप में मशहूर हैं। साल 2004 में सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कई बड़े सरकारी और सैन्य समारोहों में हिस्सा लिया। 2014 से उन्होंने महिला यूनिट की कमान संभाली और कई हाई-प्रोफाइल परेड में नेतृत्व किया। वे चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी हैं। चीन में उन्हें अनुशासन और सैन्य छवि का बड़ा चेहरा माना जाता है।

जेनिफर जेंग के दावों पर कितना भरोसा?

जेनिफर जेंग पहले भी चीन को लेकर कई बड़े और विवादित दावे कर चुकी हैं। इस मामले में भी उन्होंने कोई आधिकारिक सबूत पेश नहीं किया है। न तो चीन सरकार और न ही किसी स्वतंत्र एजेंसी ने यह पुष्टि की है कि डिनर में मौजूद महिला सच में चेंग चेंग थीं। कई लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया थ्योरी मान रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स का कहना है कि तस्वीरों में काफी समानता दिखती है। फिलहाल यह मामला पूरी तरह आरोप और अटकलों के स्तर पर ही बना हुआ है।

चीन की जासूसी रणनीति पर फिर चर्चा

इस विवाद के बाद एक बार फिर चीन की कथित जासूसी रणनीतियों पर चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका में पहले भी कई बार चीनी एजेंटों पर

नीट रि-एक्जाम के लिए अरविंद केजरीवाल की सभी सीएम से खास अपील, बिहार-हरियाणा के कदम को सराहा

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ठएएळ री-एग्जाम देने जा रहे छात्रों के हक में एक बड़ी अपील की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों (उट) से आग्रह किया है कि वे 21 तारीख को होने वाली ठएएळ पुनर्परीक्षा के लिए छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त करें।

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पंजाब की पहल के बाद अब बिहार और हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्यों में छात्रों को यह सुविधा दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जल्द ही ऐसा ही फैसला लेंगे। आइए जानतें हैं देश के अन्य राज्यों में इस परीक्षा को लेकर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं...

20 और 21 जून को फ्री मिलेगी बस सेवा

पंजाब सरकार द्वारा छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने राज्य के ठएएळ परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है।

2 दिन मुफ्त यात्रा: हरियाणा रोडवेज की बसों में छात्र 20 और 21 जून को बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड ही टिकट: परीक्षा केंद्र तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने के लिए छात्रों को बस कंडक्टर को केवल अपना वैध एडमिट कार्ड (अ्रेड उं१ि) दिखाना होगा।

पुरानी परंपरा को दोहराया: मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार छात्रों के तनाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (उएळ) के दौरान भी ऐसी सुविधा दी गई थी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं।

बिहार में भी ठएएळ

परीक्षार्थियों को राहत

पेपर लीक विवाद और मानसिक तनाव से जूझ रहे बिहार के मेडिकल परीक्षार्थियों के लिए भी राहत की खबर आई है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम (BSRTC) राज्य भर में परीक्षा देने वाले छात्रों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करेगा।

लाखों परिवारों को आर्थिक राहत: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इस मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इससे दोबारा परीक्षा देने जा रहे छात्रों के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

3 मई की परीक्षा हुई थी रद्द: ज्ञात हो कि 3 मई को देश भर में आयोजित हुई ठएएळ-वऋ परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद मचे हंगामे के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा परीक्षा कराई जा रही है।

बस स्टैंड्स और सेंटर्स पर प्रशासन के विशेष इंतजाम

भीषण गर्मी और छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बुनियादी सुविधाएं: रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और परीक्षा केंद्रों के पास छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पीने का साफ पानी, छांव की व्यवस्था और 'सत्तू' जैसी पारंपरिक खान-पान की चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त बसें और सुरक्षा व्यवस्था: परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। परीक्षा केंद्रों वाले प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले छात्रों को कोई असुविधा न हो।

दरअसल, मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली NEET UG 2026 की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बीते 3 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा को पेपर लीक विवाद के बाद सरकार की मंजूरी से 12 मई को रद्द कर दिया गया था। अब इस देशव्यापी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के लिए तारीखों और नियमों की घोषणा कर दी गई है। इस बार देश और विदेश के विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा पूरी तरह पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जाएगी। इस बार छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे

एनटीए द्वारा जारी नए टाइमटेबल के अनुसार, योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए परीक्षा शेड्यूल को नोट कर सकते हैं। इस बार छात्रों की सहूलियत के लिए परीक्षा के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है।

परीक्षा की तारीख: 21 जून, 2026

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 तक

अतिरिक्त समय: परीक्षा के तनाव को देखते हुए इस बार छात्रों को पेपर पूरा करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।